

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 1974/वैशाख 11, 1896

No. 106]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 1974/VAISAKHA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 मई, 1974

सं० 11/35/74—कार्यान्वयन सैल—केन्द्रीय सरकार के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी असैनिक कर्मचारियों से संबंधित तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्णय वित्त मंत्रालय के संकल्प संख्या 70(34)/74—कार्यान्वयन सैल, तारीख 1 नवम्बर, 1974 में अधिसूचित किए गए हैं। अब भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं/पदों और अखिल भारतीय सेवाओं की इस श्रेणी के भी वेतनमान, भत्ते, सेवा निवृत्ति, लाभ आदि से संबंधित आयोग की सिफारिशों पर भली भांति विचार किया है और इन अधिकारियों के संबंध में पूर्वोक्त मामलों पर आयोग की सिफारिशों को मोटे तौर पर निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय किया है :—

I. केन्द्रीय प्रथम I श्रेणी सेवाओं/पदों के वेतनमानों के संबंध में सिफारिशें

- (1) सभी केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं/पदों के वरिष्ठ वेतनमान का न्यूनतम, जहां कहीं भी आयोग द्वारा इसकी सिफारिश 1050 रु० की गई है, बढ़ाकर 1100 रु० किया जाए।

- (2) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन वृद्धियां लेने के लिए सेवा काल पर प्रतिबन्ध की अवधि के बारे में, जहां कहीं भी आयोग ने सिफारिशें की हैं, उसे हटा दिया जाए ।
- (3) हालांकि कुछ केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं में प्रवरण ग्रेड की व्यवस्था के लिए आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की जाएंगी, फिर भी विभिन्न केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं में ऐसे ग्रेड की व्यवस्था करने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, प्रत्येक सेवा/संवर्ग में इस ग्रेड की नफरी का निर्धारण उस सेवा/संवर्ग में संवर्ग संरचना, पदोन्नति अवसर आदि की व्यापक जांच/समीक्षा के बाद किया जाएगा ।
- (4) जहां कहीं भी आयोग ने वर्तमान वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड / विभागाध्यक्ष या समकक्ष ग्रेड में पदों के लिए 2250—2500 रु० और 2500—2750 रु० के दो वेतनमानों की सिफारिशें की हैं, 2500—2750 रु० के वेतनमानों के पदों की संख्या किसी भी सेवा विशेष में उन पदों की संख्या का 50% होगी ।
- (5) संवर्ग समीक्षा समिति प्राथमिकता के आधार पर जहां कहीं भी आवश्यक हो, इन सेवाओं में पदोन्नति अवसर सुधारने की दृष्टि से विभिन्न केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं को संवर्ग नफरी की समीक्षा करेगी ।
- (6) हालांकि केन्द्रीय प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को विशेष वेतन की मंजूरी के लिए आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की जाएंगी परन्तु श्रम सार्वजनिक के कार्य या अनिवार्य योग्यताओं के अतिरिक्त विशेषज्ञ योग्यताओं और विशिष्ट योग्यता अपेक्षित कार्य के लिए तकरीफी सेवाओं के अधिकारियों की विशेष वेतन की मंजूरी को भी सिद्धांतरूप में स्वीकार कर लिया है ।
- (7) विभिन्न केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं के अधिकारी केन्द्रीय पत्रिका में नियुक्ति के पात्र होंगे ।

II. अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमानों पर सिफारिशें

- (1) भारतीय प्रशासन सेवा के द्वारे में उस सेवा में प्रवरण ग्रेड की नफरी का निर्धारण करने वाले वर्तमान नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । इस संबंध में

भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि राज्य संवर्ग में विशेष वेतन मंजूरी के पात्र पदों की संख्या राज्य सरकार के अधीन (सुपर टाइम वेतनमान के पदों को छोड़कर) वरिष्ठ पदों के 50% से अधिक न हो।

- (2) भारतीय पुलिस सेवा का वरिष्ठ वेतनमान 1200—1700 रु० होगा और प्रवरण ग्रेड 1800 रु० (नियत) होगा। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि राज्य संवर्ग में विशेष वेतन मंजूरी के पात्र पदों की संख्या राज्य सरकार के अधीन (सुपर टाइम वेतनमान के पदों को छोड़कर) वरिष्ठ पदों के 50% से अधिक न हो।

- (3) वन पाल के वेतनमान और भारतीय वन सेवा में उप-वनपाल या वनपाल के स्तर से ऊपर प्रवरण ग्रेड के बारे में निर्णय की घोषणा बाद में की जाएगी।

III. अन्य मामलों के संबंध में सिफारिशें

- (1) द्वितीय से चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों के संबंध में स्वीकृत सुधारों को केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं पदों और अखिल भारतीय सेवाओं पर जहां कहीं प्रयोज्य हों, लागू करने के बाद वेतन निर्धारण, भत्ता मंजूरी, सेवा निवृत्ति लाभ, प्रमावी होने की तारीख आदि के बारे में आयोग की सिफारिशें मोटे तौर से स्वीकार की जाएंगी।
- (2) वर्तमान द्वितीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को आशा है कि प्रथम श्रेणी और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी उस बकाए की कुल रकम को अपने भविष्य निधि खाते में विशेष जमा करेंगे, जो उन्हें इन सिफारिशों के कारण 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक की अवधि की मिलती हो। परन्तु अंशदायी भविष्य निधि में इस प्रकार की जमा की गई रकम पर सरकार का तदनुसूची अंशदान नहीं होगा।
- (3) इस संकल्प के साथ संलग्न विवरण पत्र के कालम 1 में उल्लिखित केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं/पदों से संबंधित आयोग की सिफारिशों पर तदनुसार सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को उसके कालम 2 में दर्शाया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में इन निर्णयों को जैसे भी ये उन पर लागू हों, लागू करने के लिए इन सेवाओं के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध

प्रथम श्रेणी अधिकारियों से संबंधित तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णयों का विवरण-पत्र (इस विवरण-पत्र में जिन अध्यायों तथा पैराग्रों का उल्लेख किया गया है, वे आयोग की रिपोर्ट के हैं)।

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

वेतन

1. सरकार के अधीन प्रथम श्रेणी सेवाओं में प्रवेश पर प्रारम्भिक वेतन 700 रु० प्रतिमास होना चाहिए और अधिकतम वेतन 3500 रु० प्रतिमास की वर्तमान उच्चतम सीमा में कोई परिवर्तन करना जरूरी नहीं है।

स्वीकृत।

(संदर्भ—अध्याय 7, पैरा 21 और 37)

2. विभिन्न प्रथम श्रेणी सेवाओं/संदर्भों/पदों के वेतन-मान और विशेष वेतन अध्याय 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, और 21 से 47 तक में यथा-संस्तुत।

निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत:—

- (i) जहां कहीं भी आयोग ने 1050—1600 रु० और 1050—1800 रु० के वेतनमानों की सिफारिशें की हैं, उन्हें क्रमशः 1100—1600 रु० और 1100—1800 रु० संशोधित किया जाए।

- (ii) जहां कहीं भी आयोग ने वर्तमान खरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/विभागाध्यक्ष या समकक्ष ग्रेड पदों के लिए 2250—2500 रु० और 2500—2750 रु० के दो वेतनमानों की सिफारिश की है, वहां पर 2500—2750 रु० के वेतन-मान के पदों की किसी भी

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

सेवा विशेष में उन पदों की संख्या आयोग द्वारा यथासंस्तुत 1/3 से बढ़ा कर 1/2 किया जाए ।

(iii) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में मुख्य परियोजना अधिकारी, सलाहकार (पेट्रो रसायन) और प्रमुख, रिफाइनरी योजना एवं विकास और अन्वेषण प्रमुख के पदों का संशोधित वेतनमान 2500-2750 रु० होगा ।

3. भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय आयकर सेवा, भारतीय सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क सेवा, भारतीय डाक सेवा और सैन्य भूमि एवं छावनी सेवा पर लागू होने वाला वेतन का एकीकृत समयमान अर्थात् 400-1250 रु० को तोड़कर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अलग-अलग वेतनमान बनाए जाएं ।

स्वीकृत ।

(संदर्भ—प्रधाय 12, पैरा 7)

4. संगठित हॉलीनिथरी सेवाओं में 2000-2250 रु० का प्रवरण ग्रेड लागू किया जाए, प्रवरण ग्रेड उन्हीं अधिकारियों को स्वीकार्य होगा, जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अथवा मध्यवर्ती प्रशासनिक ग्रेड में 2,000 रु० के स्तर पर पहुंच जाते हैं और अधिकतम पर दो वर्ष तक बने रहते हैं । प्रवरण ग्रेड पदों की संख्या उन सेवाओं की संरचना की विस्तृत समीक्षा करने के बाद सावधिक रूप से निर्धारित की जानी चाहिए ।

स्वीकृत ।

[संदर्भ—अध्याय 14, पैरा 14(घ)]।

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

5. भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा में 2000— स्वीकृत ।

2250 रु० का एक प्रवरण ग्रेड बनाया जाना चाहिए । अक्तूबर 1969 में विभागीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ग्रेड की संख्या निर्धारित करे ।

(संदर्भ—अध्याय 17, पैरा 17)

6. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में 350(500) — स्वीकृत ।

900 रु० के वर्तमान ग्रेड (प्रतिस्थापन वेतनमान 775-1200 रु०) के ऊपर 900-1400 रु० का एक गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड बनाया जाए ।

(संदर्भ—अध्याय 9, पैरा 49)

विशेष वेतन

7. केन्द्रीय सचिवालय के पदों के सम्बन्ध में विशेष वेतन की स्वीकृत
बरों में परिवर्तन की कोई सिफारिश नहीं की जाती है ।

(संदर्भ—अध्याय 8, पैरा 35)

8. विभिन्न गैर तकनीकी, तकनीकी, वैज्ञानिक या इंजीनियरी स्वीकृत । इन सभी विभागों के विभागों के मुख्यालय संगठनों में नियुक्त केन्द्रीय प्रथम श्रेणी मुख्यालय संगठनों में वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों द्वारा सेवाओं के अधिकारियों को विशेष वेतन की मंजूरी । वेतनमान अधिकारियों द्वारा धारित पों पर 200 रु० प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाये । कनिष्ठ प्रशासनिक और मध्यवर्ती प्रशासनिक ग्रेडों के अधिकारियों द्वारा धारित पदों पर 300 रु० प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाए ।

[संदर्भ—अध्याय 8, पैरा 35 से 37 तक और अध्याय 14, पैरा 27 (i)] ।

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

9. प्रथम श्रेणी सेवाओं के मशरूफों द्वारा धारित कुछ क्षेत्रीय पदों पर मिलने वाले विशेष वेतन की वर्तमान दरों को उस स्तर, जिस पर विशेष वेतन स्वीकार्य की जानी चाहिए और इन सीपानों पर मिलने वाले विशेष वेतन की मात्रा दोनों के संदर्भ में युक्ति युक्त बनाया जाना चाहिए। क्षेत्रीय पदों पर, जिन पर विशेष वेतन मिलना हो, यदि वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी नियुक्त हों तो 100 रुपए प्रतिमास एक समान विशेष वेतन दिया जाना चाहिए और कनिष्ठ प्रशासनिक तथा मध्यवर्ती प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों द्वारा धारित पदों पर 200 रुपए प्रतिमास विशेष वेतन मिलना चाहिए।
(संदर्भ—अध्याय 8, पैरा 35 से 37 तक)
10. वर्तमान इस प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया जाना चाहिए कि केन्द्रीय मन्त्रिवालय में अवर सचिव तथा उप सचिव के पदों पर केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों का वेतन तथा विशेष वेतन तत्समान वरिष्ठता एवं सेवा काल के भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की स्वीकार्य वेतन तथा विशेष वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए।
(संदर्भ—अध्याय 12, पैरा 40)
11. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की द्वितीय श्रेणी का संवर्ग धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और भविष्य में की जाने वाली संपूर्ण भर्ती प्रथम श्रेणी कनिष्ठ वेतनमान की जानी चाहिए। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी अधिकारी ग्रेड II और सामान्य ड्यूटी अधिकारी ग्रेड I के पदों को उपयुक्त ढंग से प्रथम श्रेणी के कनिष्ठ और वरिष्ठ समय-मानों में रखा जाना चाहिए। वर्तमान ग्रेड II के सामान्य ड्यूटी अधिकारियों की समुचित छानबीन के बाद कनिष्ठ प्रथम श्रेणी में नियुक्त किया जाना चाहिए। जो इस प्रकार चुने नहीं जाते हैं, वे श्रेणी II में ही रहेंगे और उन्हें मानक द्वितीय श्रेणी वेतनमान दे दिया जाना चाहिए।
(संदर्भ—अध्याय 16, पैरा 7 और 8)
12. सामान्य ड्यूटी अधिकारी ग्रेड I, अस्पताल विशेषज्ञ और शिक्षण विशेषज्ञ अपने-अपने क्षेत्र में पदोन्नति के उचित अवसर प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के मरचनात्मक पुनर्गठन की आवश्यकता है।
(संदर्भ—अध्याय 16, पैरा 12)

स्वीकृत।

स्वीकृत।

स्वीकृत।

सिद्धान्त रूप में स्वीकृत।

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

13. रेसिडे चिकित्सा सेवा का द्वितीय श्रेणी संवर्ग समाप्त कर दिया जाएगा महायुक्त मंडल चिकित्सा अधिकारी नाम से एक पंयुक्त कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वेतनमान लागू किया जाए।
(संदर्भ—अध्याय 16, पैरा 24 और 25) स्वीकृत।
14. भविष्य में वेतन वृद्धि, जिस मामले में देय है, उन मामलों की पहली तारीख से ही दी जानी चाहिए।
(संदर्भ—अध्याय 8, पैरा 22) स्वीकृत।
15. केन्द्रीय सेवा प्रथम श्रेणी के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सीधी भर्ती वालों के लिए अगली वेतन वृद्धि प्रथम श्रेणी में 14 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही दी जानी चाहिए।
(संदर्भ—अध्याय 12, पैरा 17) अस्वीकृत।
16. मूल नियम 22-ग के अन्तर्गत पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के मामलों में यदि कोई कर्मचारी निचले वेतनमान का अधिकतम वेतन ले रहा हो तो उसे निचले वेतनमान के अधिकतम राशि के ऊपर एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाए (जो वेतनमान में अन्तिम वेतनवृद्धि की राशि के बराबर हो) और उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन-निर्धारण अगले सोपान में किया जाए।
(संदर्भ—अध्याय 8, पैरा 25) स्वीकृत, जहां तक द्वितीय श्रेणी पदों से प्रथम श्रेणी पर पदोन्नति का सम्बन्ध है।
17. एक प्रथम श्रेणी पद से दूसरे प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति के मामले में उच्च वेतनमान में वेतन का निर्धारण निम्न वेतनमान में लिए जा रहे वेतन से अगली सोपान पर किया जाना चाहिए, चाहे निम्न पद स्थायी हो अथवा स्थानापन्न या अस्थायी।
(संदर्भ—अध्याय 8, पैरा 27) स्वीकृत।
18. कनिष्ठ प्रथम श्रेणी वेतनमान से वरिष्ठ प्रथम श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति पर समानुक्रमणिका के अनुसार वेतन नियतन का लाभ सभी संगठित प्रथम श्रेणी सेवाओं को तथा उन सेवाओं में पदोन्नति के मामले में दिया जाना चाहिए, जिनमें कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वेतनमान हों, भले ही वरिष्ठ वेतनमान के स्तर पर भी पाश्चात् भर्ती होती हो। वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं में, जहां यह लाभ इन समय उपलब्ध है, मिलता रहना चाहिए।
(संदर्भ—अध्याय 8, पैरा 29) स्वीकृत।

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

19. वर्तमान वेतनमानों में 1800 रु० तक प्रतिमामास वेतन पाने वाले प्रथम श्रेणी अधिकारियों का जिनमें 1800 रु० प्रतिमास वेतन पाने वाले भी सम्मिलित हैं, प्रस्तावित वेतनमानों में वेतन-निर्धारण करने के लिए उनकी वर्तमान परिलब्धियों में वर्तमान वेतन (चाह वह मूल, स्थानापन्न अथवा कार्यकारी हो) का 5 प्रतिशत जोड़ा जाए जो 10 रु० से कम और 50 रु० से अधिक न हो और प्रस्तावित वेतनमानों में वेतन-निर्धारण के लिए अध्याय 67 के खण्ड ii में विनिर्दिष्ट विभिन्न अन्य शर्तों के अनुसार हो।

निम्नलिखित आशोधनों के साथ स्वीकृत :

(i) वर्तमान वेतनमान के 5 प्रतिशत की दर से संगणित न्यूनतम राशि को 10 रु० से बढ़ाकर 15 रु० कर दिया जाएगा।

(ii) जबकि किसी वर्तमान वेतन क्रम में 5 से अधिक सोपानों में वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन परिशोधित वेतनमान में उस सोपान पर निर्धारित होता है, जिस पर उनके तत्काल पूर्ववर्ती 5 क्रमिक सोपानों में वेतन पाने वाले कर्मचारियों का होता है, तब उन कर्मचारियों का वेतन, जो वर्तमान वेतनमानों में छठे से दसवें तक या इसके बीच के सोपान में, जहां तक एक सो वेतन परिशोधित वेतनमान में निर्धारित होता हो, वेतन पाते थे, परिशोधित वर्तमान में एक वेतन वृद्धि देकर बढ़ा दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि दसवें सोपान के ऊपर पन्द्रहवें सोपान तक वर्तमान वेतनमान में वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन भी पूर्व लिखित कर्मचारियों के ही बराबर परिशोधित वेतनमान में निर्धारित होता है, तो दसवें सोपान के ऊपर वाले कर्मचारियों को एक और वेतन वृद्धि दी जाएगी। इसी अनुक्रम में यदि वेतन राशि अगले सोपानों में भी एक सी बनी

बेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

20. जहाँ तक वर्तमान बेतनमानों में 1800 रु० प्रतिमास से अधिक बेतन लेने वाले अधिकारियों का प्रश्न है, प्रस्तावित बेतनमानों में उनका बेतन निघरिण मूलभूत नियम 22, 23 और संबद्ध लेखा परीक्षा निर्वेशों के अधीन किया जाना चाहिए।

(संदर्भ—अध्याय 67, पैरा 7)

21. द्वितीय श्रेणी में की गयी सेवा को कुछ तरजीह दी जानी चाहिए, कम से कम उन प्रथम श्रेणी सेवाओं में जहाँ द्वितीय श्रेणी से पदोन्नति सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ बेतनमान में होती है। किस सीमा तक और किन शर्तों के अधीन तरजीह दी जानी है, इसका निर्णय अलग-अलग विभाग करेंगे।

(संदर्भ—अध्याय 13, पैरा 10)

महंगाई भत्ता

22. जब औद्योगिक कामगारों (सामान्य) के लिए अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोजता मूल्य सूचकांक (1960-100) के 12 महीने के औसत में 8 अंक बढ़ जाएं तब 700 रु० और इससे अधिक तथा 2250 रु० प्रतिमास तक बेतन पाने वाले कर्मचारियों को 2.5 प्रतिशत की दर पर परन्तु अधिक से अधिक 20 रु० महंगाई भत्ता निम्नलिखित तरीके से दिया जाना चाहिए:—

आधार अवधि के ऊपर कीमतों में वृद्धि आधार वर्ष चारी
1960 के सूचकांक के 200 अंकों का 12 महीने का औसत जो बेतन ढाँचा तैयार करने के लिए अपनायी गई।

रहती है तो उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

स्वीकृत। बशर्ते कि 31 दिसम्बर 1972 को लागू दर पर लिया जाने वाला महंगाई भत्ता भी 1 जनवरी, 1973 से अथवा जिस तारीख से वे संशोधित बेतनमान के लिए अपना विकल्प दें, संशोधित बेतनमान में बेतन-निघरिण के लिए “वर्तमान परिलब्धियों” में शामिल किया जाए। सिद्धान्त रूप में स्वीकृत।

स्वीकृत, बशर्ते कि महंगाई भत्ते की मंजूरी की दर 3 प्रतिशत हो परन्तु 27 रु० प्रति मास से अधिक न हो।

- (1) 1960 के आधार सूचकांक के 12 महीने के औसत में पहले 8 अंकों की कीमत वृद्धि होने पर।

- (1) 900 रु० प्रतिमास तक संशोधित बेतन पाने वाले सभी कर्मचारी, उचित सीमान्त समायोजनों सहित।

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(2) सूचकांक श्रैसत में 16 अंकों की वृद्धि होने पर।</p> | <p>(2) उपर्युक्त (1) के सभी कर्मचारी तथा 1600 रु० प्रतिमास तक संशोधित वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी उचित सीमान्त समायोजनों सहित।</p> |
| <p>(3) सूचकांक श्रैसत में 24 अंकों की वृद्धि होने पर।</p> | <p>(3) उपर्युक्त (1) और (2) के सभी कर्मचारी तथा संशोधित वेतनमान में 1600 रु० से अधिक और 2250 रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी, उचित सीमान्त समायोजनों सहित।</p> |

जब कभी किसी भी उच्च वेतन श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रारम्भिक रूप में महंगाई भत्ता योजना के अंतर्गत लाया जाता है, तो उस श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाने वाला कुल महंगाई भत्ता, पहले से महंगाई भत्ता योजना के अधीन आई हुई श्रेणियों के सर्वोच्च वेतन श्रेणी को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते से कम नहीं होना चाहिए। जब सूचकांक श्रैसत 24 अंकों से बढ़ जाए तो कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियां महंगाई भत्ता योजना के अधीन उसी प्रकार शामिल की जानी चाहिए, जिस प्रकार 8 अंकों की पहली वृद्धि के समय की गयी थी और इसकी पुनरावृत्ति की जाती रहे। वेतन और महंगाई भत्ते का जोड़ किसी भी मामले में 2400 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं होना चाहिए।

(संदर्भ—अध्याय 55, पैरा 6, 7, 8, 14 और 15)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>23. महंगाई भत्ते के परिणामस्वरूप दी जाने वाली राशि को निकटतम 10 पैसे के पूर्णांक में परिवर्तित कर लिया जाए।</p> | <p>स्वीकृत।</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

(संदर्भ—अध्याय 55, पैरा 19)

प्रतिपूरक भत्ता

प्रतिपूरक (नगर) भत्ता

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>24. प्रतिपूरक (नगर) भत्ता ऐसे कर्मचारियों को अनुभूत होना चाहिए, जिनके कार्य-स्थान, 1971 के जनगणना के</p> | <p>स्वीकृत।</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

लिए अपनाए गए नगर अथवा कस्बे के “सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र” के अंतर्गत कहीं भी आते हों। किसी शहर का श्रेणी निर्धारण करने के लिए सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को एक इकाई के रूप में भी माना जाना चाहिए।

(संदर्भ—अध्याय 56, पैरा 12)

25. प्रतिपूरक (नगर) भत्ता निम्नलिखित दरों पर दिया जाए :—

नगर/कस्बे की श्रेणी

प्रतिपूरक नगर भत्ते की दरें

‘क’ श्रेणी	700 रु० तथा उससे ऊपर	वेतन का 6 प्रतिशत, जो 75 रु० प्रतिमास से अधिक न हो।
‘ख-1’ श्रेणी	700 रु० तथा उससे ऊपर	वेतन का 4.5 प्रतिशत, जो 50 रु० प्रतिमास से अधिक न हो।
‘ख-2’	700 रु० और उससे ऊपर परन्तु 750 रु० से नीचे	वेतन का 3.5 प्रतिशत, जो 10 रु० प्रतिमास से अधिक न हो।
	750 रु० तथा उससे ऊपर	उसका वेतन 759 रु० से जितना कम हो।

‘ग’ श्रेणी कोई भत्ता नहीं।

(संदर्भ—अध्याय 56, पैरा 13)

स्वीकृत, परन्तु जहाँ परिशोधित दरें लागू करने के परिणामस्वरूप, किसी वर्तमान कर्मचारी को हानि हो तो उसको अनुमत्य वर्तमान भत्ते तथा परिशोधित दर पर अनुमत्य भत्ते के अन्तर को वैयक्तिक भत्ता मानकर उसको मिलने वाले वर्तमान भत्ते की राशि को संरक्षित रखा जाए। यह संरक्षण तब तक दिया जाता रहेगा जब तक कि वह कर्मचारी उसी स्थान पर कार्य करते हुए परिशोधित दरों के अनुसार, पदोन्नति पर अथवा अन्यथा प्रतिपूरक (नगर) भत्ते की उच्चतर राशि का हकदार न हो जाए।

मकान किराया भत्ता

26. मकान किराया भत्ते की दरें नीचे दिए अनुसार होंगी :—

नगर/कस्बे की श्रेणी

मकान किराया भत्ते की दरें

- | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| (i) क, ख-1 तथा ख-2 | वेतन का 15 प्रतिशत परन्तु 400 रु० प्रतिमास से अधिक न हो। |
| (ii) ‘ग’ | वेतन का 7½ प्रतिशत परन्तु 200 रु० प्रतिमास से अधिक न हो। |

[संदर्भ—अध्याय 56, पैरा 29 (iii)]

स्वीकृत।

वेतन आयोग को सिफारिशें

सरकार का निर्णय

27. कोई नगर अथवा कस्बा, जो अपेक्षाकृत अलग-थलग पड़ जाने के कारण अथवा तीर्थ-स्थान होने के कारण जहाँ जनसंख्या अस्थायी तौर पर बढ़ जाया करती है अथवा जो किसी राज्य की राजधानी आदि के होने के कारण, असामान्य रूप से खर्चीली हो किन्तु जनसंख्या के आधार पर प्रतिपूरक (नगर) भत्ता के लिए अर्हक न हो, तो ऐसी अवस्था में गुणावगुण के आधार पर उस स्थान के बारे में खासतौर पर विचार किया जाना चाहिए।

(संदर्भ—अध्याय 56, पैरा 14)

28. प्रतिपूरक (नगर) भत्ते की मंजूरी के लिए जिस 'संपूर्ण नगरीय क्षेत्र' की अवधारणा की सिफारिश की गई है, —उसे मकान किराया भत्ते को मंजूरी के लिए लागू न किया जाए।
(संदर्भ—अध्याय 56, पैरा 30)

29. (क) सभी कर्मचारियों के लिए किराये की रसीदें देना और उनका सत्यापन अनिवार्य बना दिया जाए।

(क) स्वीकृत। किन्तु परिशोधित वेतनमानों में 750 रु० प्रति-मास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए, जिनमें नए भर्ती होने वाले कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, सत्यापन के लिए किराया-रसीदें प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(ख) किन्तु, जो कर्मचारी इस समय किराया-रसीदें दिए बिना मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह सुविधा तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे उसी मकान किराया भत्ते का दावा प्रस्तुत करते रहें, जो उन्हें इस समय मिल रहा है। यह रियायत नए भर्ती होने वालों पर भी लागू होनी चाहिये।

[संदर्भ—अध्याय 56, पैरा 29(iv)]

(ख) स्वीकृत। वशतें कि मकान किराया रसीद के प्रस्तुतीकरण में छूट से संबंधित वर्तमान नियमों का पालन हो। किन्तु नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर उपर्युक्त (क) में दिया गया निर्णय लागू होगा।

वेतन आयोग की सिफारिश

सरकार का निर्णय

सरकारी आवास के लिए किराया

30. आवास के प्रयोजन के लिए सरकार मकान का किराया स्वीकृत ।

लिए जाने के निमित्त वेतन का प्रतिशत अपरिवर्तित रहेगा ।

(संदर्भ—अध्याय 56, पैरा 44)

पर्वतीय स्थान प्रतिपूरक भत्ता

31. पर्वतीय स्थान प्रतिपूरक भत्ते की मंजूरी के लिए उस स्थान की ऊंचाई को ही आधार माना जाना चाहिए । कर्मचारियों को पर्वतीय स्थान प्रतिपूरक भत्ता निम्नलिखित दरों पर दिया जाना चाहिए :—

स्थान	प्रतिमास वेतन	पर्वतीय स्थान प्रतिपूरक भत्ते की दर
(i) 1500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थान	700 रु० और उससे अधिक	वेतन का 6% जो 75 रु० प्रति मास से अधिक न हो ।
(ii) 1000 मीटर या उससे अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थान	700 रु० और उससे अधिक	वेतन का $4\frac{1}{2}\%$ जो 50 रु० से अधिक न हो ।

स्वीकृत । परन्तु जहाँ परिशोधित दरें लागू करने के परिणाम-स्वरूप किसी वर्तमान कर्मचारी को हानि होती हो, तो उसको अनु त्व वर्तमान भत्ते तथा परिशोधित दर पर अनुसृत्य भत्ते के अंतर को वैयक्तिक भत्ता मानकर उसको मिलने वाले वर्तमान भत्ते की राशि को संरक्षित रखा जाए । यह संरक्षण तब तक दिया जाता रहेगा जब तक कि वह कर्मचारी उसी स्थान पर कार्य करते हुए परिशोधित दरों के अनुसार पदोन्नति पर अथवा अन्यथा प्रतिपूरक (नगर) भत्ते की उच्चतर राशि का हकदार न हो जाए ।

(संदर्भ—अध्याय 56, पैरा 56 और 57)

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

शीतकालीन भत्ता

32. 1250 रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को निम्नलिखित दरों से शीतकालीन भत्ता दिया जाना चाहिए ।

स्वीकृत ।

स्थान	प्रतिमास वेतन	शीतकालीन भत्ते की दरें
(i) 1500 मी० या उससे अधिक	700 रु० और उससे अधिक परन्तु 1250 रु० तक	वेतन का 6% जो 40 रु० प्रतिमास से अधिक न हो ।
स्थित पर्वतीय स्थान		
(ii) 1000 मी० या उससे अधिक	700 रु० और 1250 रु० किन्तु 1500 तक	वेतन का 4½%, जो 25 रु० प्रतिमास से अधिक न हो ।
स्थित पर्वतीय स्थान		

(संदर्भ—अध्याय 56, पैरा 58)

विषम जलवायु भत्ता

33. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की उन्हीं स्थान पर विषम जलवायु भत्ता देने को वर्तमान प्रणाली जारी रखनी चाहिए जहां राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को इसी प्रकार का भत्ता देती हैं । उन सभी क्षेत्रों में, जिन्हें विषम जलवायु वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, 900 रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को श्रेणी ख-1 नगरों में अनुमत्य प्रतिपूरक (नगर) भत्ते के लिए लागू दर के अनुसार विषम जलवायु भत्ता दिया जाना चाहिए ।

(संदर्भ—अध्याय 56, पैरा 61)

स्वीकृत । परन्तु जहां परिशोधित दरें लागू करने के परिणाम-स्वरूप किसी वर्तमान कर्मचारी को हानि हो, तो उसको अनुमत्य वर्तमान भत्ते तथा परिशोधित दर पर अनुमत्य के अन्तर को वैयक्तिक भत्ता मानकर उसको मिलने वाले वर्तमान भत्ते की राशि को संरक्षित रखा जाए । यह संरक्षण तब तक दिया जाता रहेगा जब तक कि वह कर्मचारी

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार की निर्णय

उसी स्थान पर कार्य करते हुए परिशोधित दरों के अनुसार पदोन्नति पर अथवा अन्यथा प्रतिपूरक (नगर) भत्ते की उच्चतर राशि का हकदार न हो जाए।

परियोजना भत्ता

34. आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 56, पैरा 62 से 65 तक सिद्धांत रूप से स्वीकृत।
में अविकसित और दुर्गम स्थानों पर प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण कार्य में संलग्न केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को परियोजना या निर्माण कार्य भत्ते की परिशोधित दरें और कुछ शर्तें निर्धारित करने के संबंध में सिफारिश की है।

यात्रा भत्ता

35. रिपोर्ट के अध्याय 57 में यात्रा भत्ता संबंधी निम्नलिखित स्वीकृत।
मामलों में दरों और/अथवा शर्तों के बारे में आयोग ने अपनी सिफारिशों की हैं :—
- (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का श्रेणीकरण
 - (ख) मील भत्ता-वातानुकूलित (शायिका) या वायुयान द्वारा यात्रा की हकदारी सहित
 - (ग) सवारी भत्ता
 - (घ) ऐसे स्थानों के लिए दैनिक भत्ता जहां कर्मचारी को होटल आदि में निर्धारित दरों पर भोजन और/या आवास की व्यवस्था उपलब्ध हो
 - (ङ) स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते की स्वीकृति के लिए परिवार की परिभाषा
 - (च) स्थानान्तरण अनुदान
 - (छ) स्थानान्तरण संबंधी प्रासंगिक व्यय
 - (ज) असबाब भत्ता
 - (झ) सेवा निवृत्ति / मृत्यु होने पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता
 - (ट) सैनाती के स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर पढ़ने वाले बच्चों का यात्रा भाड़ा।

भेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

छुट्टी यात्रा रिआयत

36. (क) दो वर्ष के काल खण्ड (ब्लॉक) में एक बार स्थायी निवास स्थान की यात्रा की वर्तमान व्यवस्था इस आशोधन के साथ जारी रहे कि चार वर्ष के काल खण्ड में एक बार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रिआयत दी जाए, बशर्ते कि वर्तमान व्यवस्था में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी होती हों। स्थायी निवास स्थान के प्रतिरिक्त अन्य स्थान की यात्रा के लिए रिआयत की सुविधा उन कर्मचारियों को भी दी जाए, जिनका स्थायी निवास स्थान 400 कि० मी० के अन्दर हो। स्वीकृत।
- (ख) छुट्टी यात्रा रिआयत के लिए परिवार की परिभाषा वहीं होनी चाहिए, जिसकी सिफारिश आयोग ने स्थानान्तरण पर की जाने वाली यात्रा के संबंध में यात्रा भत्ता के लिए की है। स्वीकृत।
- (ग) कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी में भी यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रिआयत की अनुमति दी जानी चाहिए और इसके लिए अनुपस्थिति की न्यूनतम अवधि की शर्त नहीं होनी चाहिए। स्वीकृत।
- (संदर्भ—अध्याय 58, पैरा 12, 13 और 14)

शिक्षा सुविधाएं और भत्ते

37. (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा भत्ते और शिक्षा सुविधाओं के संबंध में आयोग ने कुछ वरों और / या शर्तों की सिफारिश की है। स्वीकृत।
- (संदर्भ—रिपोर्ट का अध्याय 59)
- (ख) रेलवे विभाग की तरह अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए भी बच्चों का शिक्षा भत्ता केवल तभी अनुमत्य होगा जब सरकारी कर्मचारी को तैनाती के स्थान पर अपेक्षित स्तर का स्कूल न हो अथवा उस स्कूल में भर्ती के लिए स्थान उपलब्ध न हो। स्वीकृत।
- (संदर्भ—अध्याय 59, पैरा 9)

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

मृत्यु तथा निवृत्ति लाभ

38. (क) पेंशन और मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान की संगणना करने के वर्तमान सूत्र (फार्मुले) में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। किन्तु पेंशन तथा उत्पादन के लिए ग्रहण सेवा की अधिकतम अवधि 30 वर्ष से बढ़ा कर 33 वर्ष कर दी जाए। पेंशन मंजूरी और मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान अर्जन के लिए ऊपर की वेतन सीमा 1800 रु० से बढ़ाकर 2500 रु० की जानी चाहिए। अधिकतम पेंशन की वर्तमान उच्चतम सीमा 675 रु० से बढ़ाकर 1000 रु० और अधिकतम मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान को 24,000 रु० से बढ़ाकर 30,000 रु० की जानी चाहिए।

स्वीकृत।

(संदर्भ—अध्याय 60, पैरा 41, 43, 44, 45 और 47)।

38. (ख) वर्तमान व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी की परिवार पेंशन योजना के लिए अंशतः अंशदान करना पड़ता है, इसे जारी रहना चाहिए। हालांकि कर्मचारियों का अंशदान दो महीने की परि-लब्धियों के बराबर होते रहना चाहिए, फिर भी अधिकतम रकम 3690 रु० से बढ़ाकर 5000 रु० किया जाना चाहिए।

स्वीकृत।

(संदर्भ—अध्याय 60, पैरा 54)

(ग) परिवार पेंशन की दरें और उसकी अधिकतम सीमा में निम्नलिखित परिशोधन किया जाना चाहिए :—

स्वीकृत।

सरकारी कर्मचारी का वेतन	परिवार पेंशन की राशि
700 रु० और उससे अधिक परन्तु 1200 रु० से कम	वेतन का 15 प्रतिशत, जो 160 रु० से अधिक न हो।
1200 रु० और उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत, जो 160 रु० से कम और 250 रु० से अधिक न हो।

यदि कम से कम 7 वर्ष की नौकरी करने के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु हो, तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन बड़ी हुई दर पर, जो अन्तिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर या उपर्युक्त सामान्य परिवार पेंशन

वैतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

की दर के देने के बराबर, इनमें जो भी कम हों, अधिक से अधिक 7 वर्ष तक अथवा उस अवधि तक, जब वह 65 वर्ष का हुआ होता, यदि वह जीवित रहता, इनमें जो भी अवधि कम हो, दी जानी चाहिए। यदि सेवा निवृत्ति के पश्चात् मृत्यु हो तो बड़ी हुई दर पर परिवार पेंशन की राशि, उस सामान्य वार्षिक्य निवर्तन पेंशन (अपरिवर्तित मूल्य) की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका कि सरकारी कर्मचारी वार्षिक्य निवर्तन पर हकदार होता। सेवा निवृत्ति के पश्चात् मृत्यु होने पर परिवार पेंशन सरकारी कर्मचारी के परिवार के केवल उन सदस्यों को दी जाए, जिनकी घोषणा सेवा निवृत्ति के समय की गई हो।

(संदर्भ—अध्याय 60, पैरा 55 से 58 तक)

- (घ) अशक्तता पेंशन देने की वर्तमान शर्त में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किन्तु अशक्तता पेंशन की राशि सामान्य दर से दी जाने वाली परिवार पेंशन की राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

स्वीकृत।

(संदर्भ—अध्याय 60, पैरा 60)

- (ङ) आयोग ने अध्याय 60 के पैरा 63 से 65 तक में अस्थायी और स्थायीवत् कर्मचारियों के लिये सीमान्त लाभ की स्वीकृति के लिए कुछ दरों की सिफारिश की है।

स्वीकृत।

असाधारण पेंशन

39. आयोग ने सिफारिश की है कि अध्याय 60 के पैरा 71 से 76 तक में की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली के वर्तमान उपबन्धों को सरल और तर्कसंगत बनाया जाए।

सिद्धान्त रूप में स्वीकृत।

वार्षिक्य निवर्तन की तारीख

40. सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति उनकी वार्षिक्य निवर्तन की वास्तविक तारीख के अपराह्न के बजाय उस महीने की अन्तिम तारीख के अपराह्न से प्रभावी मानी जाए जिसमें वे वार्षिक्य निवर्तमान की आयु को प्राप्त करते हैं।

स्वीकृत।

(संदर्भ—अध्याय 60, पैरा 46)

41. कर दायित्व के लिए उपदान पर छूट की सीमा भी तदनु रूपी ढंग से 24,000 से बढ़ाकर 30,000 रु० किया जाना चाहिए।

सिद्धान्त रूप में स्वीकृत।

(संदर्भ—अध्याय 60, पैरा 46)

वैतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

42. ऐसे पदों पर विशेष रूप से योग्यता प्राप्त या अनुभवहीन कर्मचारी को सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ देना जारी रहना चाहिए, यदि उन पदों पर ये योग्यताएं लोक हित में आवश्यक हों। संघ लोक सेवा आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से उन वैज्ञानिक, चिकित्सा, प्राविधिक और अन्य व्यावसायिक सेवाओं और पदों का निर्धारण किया जाना चाहिए जिनमें सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ आवश्यक समझा गया हो और सम्बद्ध भर्ती नियमों में उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन सभी उम्मीदवारों को स्वतः लाभ प्राप्त हो सके जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार भर्ती हुए हैं।

(संदर्भ—अध्याय 60, पैरा 68)

सिद्धान्त रूप में स्वीकृत।

स्वायत्त संगठनों में वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारियों को

समाविष्ट कर लेने पर उन्हें मिलने वाले लाभ

43. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय छवि अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय विश्वविद्यालय आदि जैसे स्वायत्त संगठनों में समाविष्ट हो जाने पर वैज्ञानिक कर्मचारियों को इस समय यथानुपात पेंशन तथा उपदान का जो लाभ अनुमत्य है वह तकनीकी कामियों की विभिन्न श्रेणियों को भी इस प्रकार के संगठनों में समाविष्ट होने पर मिलना चाहिए।

(संदर्भ—अध्याय 60, पैरा 25)

स्वीकृत।

भविष्य में पेंशन भोगियों को सहायता

44. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जो 1-3 1973 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हों, उनकी पेंशन की रकम चाहे क्षिती भी हो; उन्हें उनकी पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से सहायता दी जाएगी, जो 5 रु० प्रतिमास से कम और 25 रु० प्रतिमास से अधिक न हो। यह सहायता अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) के 12 महीने के औसत में 16 एक बढ़ने पर दी जाएगी। इन दरों पर पहली सहायता उस समय दी जाएगी, जब इस सूचकांक का 12 महीने का औसत 216 पर पहुंच जाएगा।

(संदर्भ—अध्याय 60, पैरा 92)

स्वीकृत। यह निर्णय उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुए हों।

कार्य घंटे

45. (क) सामान्यतया सरकार के अधीन आने वाले औद्योगिक स्थापनाओं में एक सप्ताह के कुल कार्य घंटे 48 और एक दिन के 8 होने चाहिए, किन्तु इस 8 घंटे की अवधि में कामगारों को भोजन के लिए आधे घंटे की छुट्टी दी जानी चाहिए। इस प्रकार प्रति सप्ताह केवल 45

(क) और (ख) : वर्तमान कार्य घंटों में न तो प्रभासकीय कार्यालयों में कोई परिवर्तन होगा और न सरकारी औद्योगिक स्थापनाओं में ही।

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

कार्य घटे रह जाते हैं, जिन औद्योगिक स्थापनाओं में प्रति सप्ताह निम्न कार्य घटे 45 से कम हों, उनकी स्थिति की समीक्षा की जाए।

- (ख) प्रशासकीय कार्यालयों में प्रतिदिन निर्धारित कार्य-घटे 7 होंगे, किन्तु इसमें भोजन अवकाश शामिल नहीं होगा।

(संदर्भ—अध्याय 61, पैरा 13 और 15)

छुटियां

46. (क) कर्मचारियों के किसी भी वर्ग को एक वर्ष में 16 दिन से अधिक सार्वजनिक छुटियों की अनुमति न दी जाए। स्वीकृत।
(संदर्भ—अध्याय 61, पैरा 28)
- (ख) 16 सार्वजनिक छुटियों में से कोई छुट्टी रविवार या द्वितीय शनिवार को पड़ने पर किसी एक प्रतिबन्धित छुट्टी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की पद्धति यथाशीघ्र समाप्त कर देनी चाहिये। स्वीकृत।
(संदर्भ—अध्याय 61, पैरा 29)
- (ग) प्रतिबन्धित छुट्टियों की प्रणाली में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, किन्तु प्रतिबन्धित छुट्टी वाले त्योहारों की संख्या नियमित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। स्वीकृत।
(संदर्भ—अध्याय 61, पैरा 30)
- (घ) उन कर्मचारियों के संबंध में सार्वजनिक छुट्टी की संख्या में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, जो केवल 3 राष्ट्रीय छुट्टियों या 9 प्रभाषी छुट्टियों के हकदार हैं। स्वीकृत।
(संदर्भ—अध्याय 61, पैरा 31)

आकस्मिक छुट्टी

47. आकस्मिक छुट्टी की वर्तमान माछा पर्याप्त है। प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारी, जिन्हें प्रशासकीय कार्यालयों के कर्मचारियों को मिलने वाली सार्वजनिक छुट्टियों की तुलना में कम छुट्टियां मिलती हैं, उन्हें 15 दिन की आकस्मिक छुट्टियां मिलनी चाहिए। कर्मचारियों के किसी भी वर्ग को एक कैलेण्डर वर्ष में 15 दिन से अधिक आकस्मिक छुट्टियां न दी जाएं। जहां तैनाती स्थान की दूरी के कारण अधिक आकस्मिक छुट्टियां दी जाती स्वीकृत।

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

हैं, वहाँ यदि कोई कर्मचारी आकस्मिक छुट्टी पर जाए तो उसे एक या दो दिन का यात्रा समय दे दिया जाए, बजाए इसके कि प्रति वर्ष नियमित रूप से उसे अधिक आकस्मिक छुट्टी दी जाए।

(संदर्भ—अध्याय 61, पैरा 35 और 36)

छुट्टी की हकबारी

48. (क) गैर औद्योगिक कर्मचारियों की छुट्टी अर्जित करने की दर, अर्जित छुट्टी एकत्र होने की सीमा और एक समय की गई अर्जित छुट्टी की सीमा में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के बीच प्रथम वर्ष में छुट्टी अर्जित करने के वर्तमान अन्तर को समाप्त कर देना चाहिए। स्वीकृत।
- (ख) आधी वेतन छुट्टी के दौरान छुट्टी तनखा पर 750 रु० की वर्तमान सीमा को समाप्त कर देना चाहिए। स्वीकृत।
- (ग) सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान परिणत छुट्टी की 240 दिन की वर्तमान सीमा हटा दी जानी चाहिए। यदि किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए अर्ध-वेतन छुट्टी ली जाये तो सम्पूर्ण सेवा अवधि में अधिक से अधिक 180 दिन की ऐसी छुट्टी को परिणत कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। स्वीकृत।
- (घ) भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए अध्ययनार्थ छुट्टी नियमावली में की गई विशेष व्यवस्था को प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विशेषज्ञ तथा तकनीकी के और अधिक श्रेणियों के कामियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। स्वीकृत।
- (ङ) भारत में किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान परिलब्धियों का विनियमन अर्जित छुट्टियों के समान तरीके से किया जाना चाहिए बशर्ते कि परिलब्धियाँ उस वेतन से अधिक न हों, जिसे यदि अधिकारी ड्यूटी पर रहा होता तो अन्यथा लेता रहता हो। स्वीकृत।
- (च) भारत से बाहर उपलब्ध की गई अध्ययनार्थ छुट्टी से संबंधित उपबन्ध को जारी रखा जाना चाहिए। विदेशों में अनुमत्य अध्ययन भत्ते की दरों की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जानी चाहिए। स्वीकृत।

वेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

- (छ) सेवा अवधि में मृत्यु हो जाने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को, यदि मृत्यु की तारीख पर कर्मचारी अर्जित छुट्टी पर जाता तो उसे जितनी छुट्टी वेतन मिलती, उसके बराबर नकद रकम दी जाए, किन्तु यह रकम 120 दिन के छुट्टी वेतन की राशि से अधिक न हो।

(संदर्भ—अध्याय 62, पैरा 14, 15, 18, 19, 20 से 26 तक और 37)

विविध

49. (क) नर्सिंग स्टाफ को इस समय अनुमत्य भेस भत्ता उनके वेतनमान में सम्मिलित कर देना चाहिए और अलग से न दिया जाना चाहिए। इन कर्मचारियों को भी उन्हीं दरों से पूरा महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता (जहां कहीं अनुमत्य हो) दिया जाना चाहिए, जिन दरों से अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है।

(संदर्भ—अध्याय 16, पैरा 90)

- (ख) वर्दी भत्ते की दर बढ़ाकर प्रथम श्रेणी वेतनमान की मैट्रन के लिए 200 रु० प्रतिवर्ष कर दी जानी चाहिए।

(संदर्भ—अध्याय 16, पैरा 90 और 93)

वेतनमानों और पेंशन लाभों के लागू होने की तारीख

50. विभिन्न प्रथम श्रेणी संबंधी/सेवाओं/पदों के लिए जिन वेतनमानों की सिफारिश की गई है, वे पहली मार्च, 1973 से लागू होंगे।

(संदर्भ—अध्याय 67, पैरा 1)

अनुबंध की क्रम सं० 1 से 3 तक में उल्लिखित सिफारिशों पर किए गए निर्णय 1 जनवरी, 1973 से लागू होंगे। जिन पदों का ग्रेड बढ़ाकर 3000 रु० (नियत) या इससे अधिक वेतनमान किया गया है, उनके वेतनमानों के संशोधन की तारीख सरकार के निर्णयानुसार तारीख होगी।

51. (क) पेंशन लाभ संबंधी सिफारिशें उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगी जो पहली मार्च, 1973 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुए हों।

(क) और (ख). अनुबंध की क्रम संख्या 38 पर उल्लिखित सिफारिशों पर निर्णय

बेतन आयोग की सिफारिशें

सरकार का निर्णय

(ख) इन कर्मचारियों के संबंध में पेंशन के लाभ की संगणना के लिए परिलब्धियों में बेतन और मंहगाई धन (जहां कहीं लागू हों) के अतिरिक्त 1 मार्च, 1973 से पूर्व लिया जाने वाला मंहगाई भत्ता और अल्टरिम राहत भी शामिल की जानी चाहिए। (संदर्भ—अध्याय 67, पैरा 2)	1 जनवरी, 1973 से लागू होगा और पेंशन लाभ की संगणना के लिए परिलब्धियों से संबंधित सिफारिश भी उसी तारीख से लागू होगी।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों तथा अन्य संबंधितों को प्रेषित की जाए।

उपायुक्त, अपर सचिव।